

अध्याय-7 (Vol-1)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती

Golden Jubilee of Bank Nationalisation

वर्ष 2019 में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 50वाँ वर्ष पूर्ण हुआ, इसलिये यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत से ही भारत ने आर्थिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जिससे भारत का स्थान विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है कति अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत का बैंकिंग क्षेत्र उस अनुपात में विकसित नहीं हो पाया है।

भूमिका:

- भारत की अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से इसके बैंक अनुपातिक रूप से छोटे तथा कम क्षमता वाले हैं। वर्ष 2019 में जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत का सरिफ भारतीय स्टेट बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों की श्रेणी में 55वें स्थान पर है वहीं शीर्ष 100 बैंकों में चीन के 18 बैंक शामिल हैं।
- किसी भी देश को आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने के लिये एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की साख वृद्धि में वर्ष 2013 के बाद से न केवल तेजी से गिरावट दर्ज की गई बल्कि वर्ष 2016 के बाद यह क्षेत्र शथिल भी हो गया है। वहीं वर्ष 2010-19 के बीच नए नजी बैंकों (New Private Banks) ने प्रतिवर्ष 15-29% के बीच साख वृद्धि दर्ज की कति वर्ष 2014 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की साख वृद्धि वर्ष 2019 में एकल अंकों (4.03%) तक पहुँच गई जबकि वर्ष 2010-13 में यह 15-28% थी।
- सर्वेक्षण बताता है कि यदि भारतीय बैंकों का आकार भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात में बड़ा होता तो विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में कम-से-कम 6 बैंक भारत के शामिल होते। इसी तरह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिये भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हो सकने वाले कम-से-कम 8 भारतीय बैंकों की आवश्यकता होगी।
- चूँकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बाज़ार हस्तिदारी का 70% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने तथा इसके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का दायित्व भी इन्हीं बैंकों का बनता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में करदाताओं के 4,30,000 करोड़ रुपए से अधिक धन सरकार की इक्वटी के रूप में निवेश किया जाता है। वर्ष 2019 में पीएसबी में निवेश किये गए करदाताओं के प्रत्येक रुपए में से औसतन 23 पैसे का नुकसान हुआ। इसके विपरीत भारत में वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद 'नए नजी बैंकों' (NPBs) में निवेश किये गए निवेशक के प्रत्येक रुपए में से औसतन 9.6 पैसे का लाभ हुआ। चूँकि पीएसबी और एनपीबी एक ही घरेलू बाजार में काम करते हैं, इसलिये पीएसबी की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से अब तक

- वर्ष 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीय बैंकिंग बाज़ार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हस्तिदारी 91% थी जो वर्तमान में घटकर 70% रह गई है। PSBs की हस्तिदारी में आई 30% की गिरावट उदारीकरण के बाद नए नजी बैंकों के हस्तिसे में चली गई।
- केंद्र सरकार PSBs पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है परिणामतः बैंक की देयता के बेलआउट पर सरकार की वचनबद्धता बनी रहती है और सरकारी नियंत्रण के कारण PSBs अधिकारियों के निर्णय केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जाँच के अधीन होते हैं जिससे वे ऋण संबंधी मामलों में जोखिम लेने में सावधान रहते हैं।

राष्ट्रीयकरण के लाभ:

- ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग संसाधनों का आवंटन बढ़ा है। जैसे-वर्ष 1969-80 के मध्य की अवधि में-
 - ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ 10 गुना बढ़ी है।
 - ग्रामीण क्षेत्रों की साख में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है।
 - कृषि क्षेत्र की साख बढ़कर 40 गुना हो गई है। यह अपने शुरुआती आँकड़ों (जीडीपी का 2%) से बढ़कर वर्तमान में जीडीपी के 13% पर पहुँच गई है।
- हालाँकि उपरोक्त प्रवृत्तियों की व्याख्या में यह सतर्कता बरतनी आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण ही इन सब के लिये पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है,

जबकि इस समयावधि में हरति क्रांति, गरीबी नविवरण कार्यक्रम (जैसे- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) और RBI द्वारा अपनाई गई नीतियाँ भी इसके लिये जम्मेदार हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमज़ोर होना:

- वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सकल एवं नविल NPA क्रमशः 7.4 लाख करोड़ रुपए और 4.4 लाख करोड़ रुपए दर्ज किये जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लगभग 80% है। PSBs के सकल NPA उनके सकल अग्रिम का 11.59% रहा, जो वर्ष 2018 के 14.58% से कम रहा है और सकारात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाता है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक के पर्यवेक्षी वविवरण से पता चलता है कि वर्ष 2017- 2018 में दर्ज किये गए धोखाधड़ी के 5835 मामलों में से 92.9% और लगभग 41000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी राशियों में से 85% PSBs की है।
- NPBs की तुलना में PSBs रटिर्न-ऑन-एसेट (RoA), रटिर्न-ऑन-इक्विटी (RoE) और कुछ संकेतक आदि कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (TCAR) को प्रदर्शित करने में काफी कमज़ोर साबित हुए हैं।
- PSBs में एनपीए समस्याओं के लिये एक प्रमुख वविवरण यह है कि वर्ष 2004-11 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चरण में पीएसबी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि की कति यह ऋण वृद्धि की संदग्धि गुणवत्ता थी। जब अर्थव्यवस्था की गति धीमी थी तो बैंकिंग प्रणाली के एनपीए में नाटकीय वृद्धि देखी गई।

पीएसबी की दक्षता बढ़ाना: भावी परदृश्य

- भारत के विकास संभावनाओं के प्रमुख चालक नमिनलखित हैं:
 - a. अत्यधिक अनुकूल जनसांख्यिकी (15 से 29 वर्ष की आयु के बीच 35% आबादी)
 - b. डिजिटलीकृत बुनियादी ढाँचा जसिमें JAM के तहत ववित्तीय समावेशन, आधार वविवरण पहचान प्रणाली एवं सुवकिसति मोबाइल नेटवर्क को शामिल किया गया है।
 - c. GST संरचना
- PSBs की दक्षता में सुधार करने के लिये वभिन्न समितियों जैसे- नरसमिहन समिति (वर्ष 1991 और वर्ष 1997), राजन समिति (वर्ष 2007), पी.जे. नायक समिति (2014) ने कई सुझाव दिये हैं। सर्वेक्षण में PSBs की दक्षता में सुधार लाने के लिये दो समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में फनिटेक (फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी) का उपयोग करना।
 - सभी स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (Employee Stock Option Plans- ESOPs) को बढ़ावा देना।

नोट:

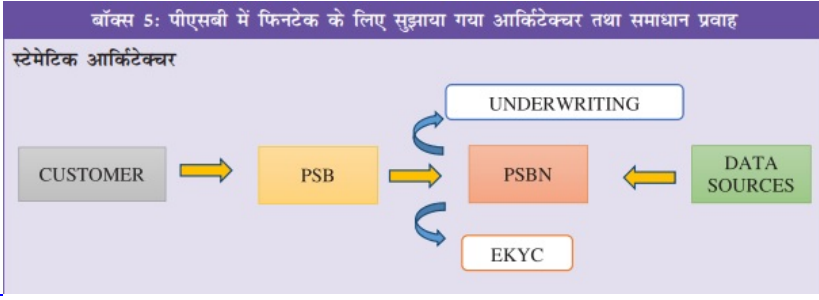
- वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के माइक्रो फाइनेंस वर्ष की घोषणा में गरीबी उन्मूलन के संबंध में MFI (Microfinance Institutions) संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया था।
- भारत में वर्ष 2016 तक की स्थिति के अनुसार, इन संस्थाओं से ऋण लेने वालों में 97% महिलाएँ थी जिनमें लगभग 30% ऋण धारक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से और 29% अल्पसंख्यक वर्ग से थे।

सार्वजनिक क्षेत्रों हेतु फनिटेक हब का निर्माण: सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग नेटवर्क

- सर्वेक्षण में बताया गया है कि वर्तमान परदृश्य को देखते हुए फनिटेक को अपनाने की जरूरत है जो वैश्विक ववित्तीय परदृश्य में क्रांति ला रहा है।
- फनिटेक पारंपरिक बैंकों को प्रभावी, कम लागत वाले बैंकिंग समाधानों के साथ आगे आने के लिये उन्हें अपने पुराने व्यापारिक प्रतमिनों की समीक्षा करने के लिये मजबूर कर रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फनिटेक से अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है क्योंकि उनका पारंपरिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी ढाँचा कुछ कोर बैंकिंग समाधानों को छोड़कर व्यापक तकनीकी युक्त नहीं है।
- फनिटेक ने बैंकों द्वारा संसाधित की जाने वाली सूचना को मौलिक रूप से बदल दिया है। जैसे- कॉर्पोरेट ऋण में मात्रात्मक आँकड़ों को नरीक्षित एवं अनरीक्षित एल्गोरिथम दोनों का उपयोग करते हुए मशीन द्वारा वविवरण किये जाते हैं।
- मशीन लर्निंग (Machine Learning- ML), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence- AI) और साथ ही बगि डेटा एवं मैचिंग जैसे उपकरण बैंकों को बड़े डेटाबेस का वविवरण करके पैटर्न को तेजी से पहचानने की क्षमता प्रदान करते हैं। वही पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह इतने कम समय में असंभव है।
- वर्तमान में पीएसबी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि उच्च परचालन लागत, मैनुअल संचालन से वविवरण प्रक्रिया प्रवाह और व्यक्तपिरक नरीणय लेना।
- उधारकर्ताओं की नगरिनी के लिये फनिटेक का प्रयोग अधिक कारगर साबित होगा। चूँकि सरकार के पास सभी पीएसबी का स्वामित्व है, इसलिये वह पीएसबी को इस डेटा को साझा करने के लिये बाध्य कर सकती है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (AI-ML) का उपयोग 'लागत-लाभ वविवरण' के आधार पर आवश्यक नरीणय करने हेतु किया जा सके।
 - सर्वेक्षण में जीएसटीएन की तरह पीएसबीएन (पीएसबी नेटवर्क) नामक इकाई की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग

वसितृत पैमाने पर एवं उधारकरत्ताओं की नगिरानी के लयि कयि जा सके ।

- पीएसबीएन का लाभ यह होगा कि इससे यह उस डेटा का प्रयोग कयि जा सकेगा जो सभी PSBs द्वारा वगित 50 वर्षों के दौरान बेहतर जोखमि नविरण समाधान का सृजन करने के लयि कयि गया है ।



PSB में कर्मचारी हसिसेदारी:

- सर्वेक्षण में बताया गया है कि मौजूदा वेतन आधारित क्षतपूरति तंत्र जोखमि उठाने के बजाय सुरक्षा एवं रूढ़िवादति को प्राथमकति देने के लयि कर्मचारियों को प्रोत्साहति करता है ।
- इस सर्वेक्षण में समाधान के रूप में यह बताया गया है कि एक कर्मचारी को मालकि बनने में सक्षम बनाने एवं सतत रूप से जोखमि उठाने तथा नवीनीकरण को अपनाने हेतु प्रोत्साहति करने के लयि सरकारी स्टॉक के एक हसिसे को कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान्स (ESOPs) के माध्यम से संगठन के सभी स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को स्थानांतरति कयि जा सकता है ।
- सर्वेक्षण यह भी अनुशंसा करता है कि PSBs को वर्तमान कर्मचारी भरती प्रक्रयि को सक्षम बनाने की ज़रूरत है जहाँ लेटरल इंट्री एवं प्रवेश स्तर पर पेशेवर रूप से प्रशिक्षति प्रतभिा की भरती की अनुमतकि की बात कही गई है ।

नषिकर्ष:

- इस प्रकार उपरोक्त सुझावों पर गंभीरता पूर्वक वचिर कर एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जानी चाहयि और बैंकगि प्रणाली में पारदर्शति एवं IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) जैसी वधिकि संरचनाओं का समावेश होना चाहयि तथा बैंकगि प्रणाली का वसितार कर देश की अर्थव्यवस्था के वकिस में सहयोग देना चाहयि ।